THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of reply to (a) & (b) above.

भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं

*507. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने-कितने सम्पूर्ण कार्यालय कार्यरत हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ग) किन-किन विभागों का कार्य इन शाखाओं को नहीं सौंपा गया है और जिसके लिए इनको अपने मुख्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण शाखा खोलने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो किस जिले में और कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ती) : (क) दर्शाये गये भारतीय रिजर्व बैंक के 13 राज्यों में 14 पूर्ण कार्यालय हैं जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :—

राज्य का नाम	स्थान
1. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2. असम	गुवाहाटी
3. बिहार	पटना
4. दिल्ली	नयी दिल्ली
5. गुजरात	अहमदाबाद
6. कर्नाटक	बंगलौर
7. केरल	त्रिवेन्द्रम
8. महाराष्ट्र	i. बम्बई
	ii. नागपुर
9. उड़ीसा	भुवनेश्वर
10. राजस्थान	जयपुर
11. तमिलनाडु	मद्रास
12. उत्तर प्रदेश	कानपुर
13. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक का भोपाल, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय कार्यालय है।

(ग) भोपाल स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय के पास सरकार के कारोबार को देखने के लिए कोई बैंकिंग विभाग और करेंसी प्रबंधन के लिये कोई निर्गम विभाग नहीं है। ये कार्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उसके नागपुर कार्यालय के पर्यवेक्षण में फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ इंदौर और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा किये जा रहे हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने भोपाल स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में बैंकिंग और निर्गम विभागों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस मामले में प्रारम्भिक कार्रवाई की जा चुकी है। इन विभागों के खोले जाने तक भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ इंदौर और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखायें सरकार के कारोबार का लेन देन जारी रखेंगी और मध्य प्रदेश राज्य के लोगों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

Excise Duty Evasion by Reliance Industries Limited

*508. **Prof. Vijay Kumar Malhotra**: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Public Accounts Committee had rapped Government for not pursuing the cases of massive excise duty evasion by Reliance Industries Limited;

(b) if so, the details thereof and the action taken to realise the Government revenue;

(c) the details of stay orders that have been obtained by R.I.L. and how much money of Government is locked therein;

(d) the steps taken to get those stay orders vacated to pave the way to realise the Government revenue; and

(e) if no steps have been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b): In the Public Accounts Committee's 155th Report (88-89—8th Lok Sabha), the Committee have made observations/recommendations in the context of Para 4.58 of the C&AG's Report for 1986-87, relating to irregular credit of Rs. 1.17 crores on base yarn by M/s. Reliance Industries Ltd. (M/s. R.I.L.). Besides, the Com-